[Shri R. L. Chaturvedi]

feasibility surveys for two corridor routes. For the suburban dispersal line, for which final location survey has been sanctioned, the work has completed up to 20 Per cent. It is from south of Dum Dum. It goes along the bank of the Circular Canal and then along the bank of Hooghly over the Port Commissioners Railway and passes through Sobha bazar, Bara Bazar, Fairba Place and Eden Gardens and terminates near Princet Ghat.

Then there is the techno-economic feasibility survey of the railway east and west between Sealdah and Howrah, a distance of about five to six kilometers. It may have to be underground. Because of the large number of huge buildings coming in, because of the better mass rapid system, it is very essential that it may have to be underground. The North-South corridor will pass through Chittaranjan Avenue, Jawaharlal Nehru Road (Chouringhee) and Ashutosh Mukerjee Road via Kalighat towards Diamond Harbour Road.

A point was raised by Shri Indrajit Gupta that though techno-economic survey are going on, who knows, the suburban dispersal line scheme may also fail through. All these schemes are thoroughly gone into. It is naturally a very serious problem for the metropolitan cities and a final decision can be reached only when this has been studied, thoroughly gone into and all the implications are examined. But this much I can assure that Rs. 50 crores are available with us and from our side there will be no delay.

I may also point out that after the final location survey work is over, it will take four years for construction. From the date on which construction starts, according to our present estimate, it will take four years and if there is an underground railway line, the period may vary from eight to ten years.

Then, there are certain individual points about so many things.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now it is 6.30.

SHRI R.L. CHATURVEDI : Then I shall sit down.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से रेलवे बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can continue tomorrow.

———

18.32 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SHORTAGE OF HOUSES IN URBAN AREAS

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में जो शहर हैं चाहे वे छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, वहां आवास (गृह) की समस्या कितनी भयंकर है ? सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ते के अन्दर, बम्बई के अन्दर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में लोग फुटपाथ पर सोते हैं । उनके लिए कहीं जगह नहीं है और आप यह भी जानते हैं कि जिन शहरों की आबादी 1961 में 8 करोड़ थी वह आबादी 1971 तक 15 करोड़ से ज्यादा होने जा रही है । ऐसी स्थिति में शहरों में आवास की समस्या कितनी भयंकर हो सकती है, आप इसका अन्दाज लगा सकते हैं । जैसा कि मैंने कहा कि वह दिल्ली शहर हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, बम्बई हो या और बड़े बड़े शहर हों जिन्हें मेट्रोपोलिटन टाउन कहा जाता है, उनकी समस्याएं तो हैं ही, छोटे शहर जैसे कि मैं बिहार के पटना शहर से आता हूं, वहां भी यह समस्या बड़ी गंभीर है। वहां पचीस हजार सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी, हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग मकान न होने की वजह से सरकारी जमीनों पर झोंपड़ी बना कर रहते हैं । उन झोंपड़ियों को भी अभी हाल में जब वहां राष्ट्रपति शासन था तो वहां के जो ऐडवाइजर्स थे, उन्होंने उजाड़ने की कोशिश की और जब उन लोगों ने निवेदन किया कि हमारे

लिए कोई जगह की व्यवस्था कर दीजिये, तब तक हमें यहीं रहने दीजिये तो उन पर लाठियां चलाई गईं, उनको पीटा गया, औरतों को पीटा गया, मर्दों को पीटा गया। तो इस तरह की स्थिति हमारे देश में शहरों के अंदर मकानों की है। देहात के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि सवेरे मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि देहातों की स्थिति बहुत ही खराब है। शहरों में आज जैसा उन्होंने बताया है, पूरा तो सर्वे उन्होंने नहीं कराया लेकिन फिर भी जो जानकारी दी है समय समय पर उससे मालूम होता है कि 1 करोड़ 20 लाख शहर के लोगों को मकान चाहिए और देहातों में 7 करोड़ मकान चाहिए। इसी से हम अन्दाज कर सकते हैं कि हालत कितनी गम्भीर है। कुछ दिन पहले खुद हमारे देश के राष्ट्रपति ने दिसम्बर 1969 में हाउसिंग कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सचमुच में स्थिति बड़ी ही गंभीर है। खुद हमारे देश की प्रधान मन्त्री कहती हैं कि मकानों की इतनी कमी है कि हमें सोचना पड़ेगा और शायद सरकार सोच भी रही है कि तमाम लोगों को फ्लेट में हम ले जायं। तो एक तरफ तो यह कहा जाता है, समाजवाद की बात कही जाती है लेकिन हमारे मिनिस्टर्स, बड़े बड़े देश के इजारेदार, पूंजीपति और पैसे वालों की हालत क्या है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के अन्दर बड़े शहर हों, छोटे शहर हों, समस्या बड़ी गंभीर है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने क्या किया जरा इस तरफ मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का और देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले 18 वर्षों में इन्होंने देहातों और शहरों में टोटल 327.18 करोड़ रुपया खर्च किया। इसमें केवल 11 करोड़ 71 लाख रुपया देहातों में खर्च किया गया, खेत मजदूरों के लिए खर्च किया गया, जिनके लिए समाजवाद सबसे जरूरी है। लेकिन समाजवाद का नाम लेते हैं, रिवाल्विंग फण्ड बनाते है और उदाहरण देते हैं कि देखो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 करोड़ के रिवाल्विंग फण्ड से 60 करोड़ रुपया कमाया, बड़े बड़े पैसे वालों को किराये पर देकर कमाया। और आप जानते हैं कि दिल्ली के अन्दर 15 लाख झुग्गी झोपड़ी वालों को भारतीयकरण का नारा देने वाले जनसंघ के प्रशासक उजाड़ रहे हैं, दिल्ली से बाहर उनको निकाल रहे हैं। दिल्ली के अन्दर ऐसी ऐसी बस्तियां बन। हुई हैं जिन्हें अनएथोराइज्ड कोलोनीज के नाम से उजाड़ा जाता है और उनको वहां से निकाला जाता है। आप कभी जमुना पार चले जाइये, दिल्ली के बहुत सारे मुहल्लों में चले जाइए, वहां रहने वाले को नोटिस दिये जा रहे हैं। भारतीयकरण का नारा देने वाले ये जनसंघी उनसे कहते है कि आपको यहां से छोड़ना है। एक तरफ उनका भारतीयकरण का नारा है लेकिन उनके भारतीयकरण के नारे के पीछे गरीबों को उजाड़ने का नारा है। उनका मतलब यही है कि अमीरों को बसाओ, पांच करोड़ से 60 करोड़ कमाओ धनी लोगों को मकान देकर, उनकी नो यह नीति है। लेकिन आप तो समाजवाद की बात बोलते हैं, आपने पैसे खर्च किए पिछले दिनों में 327.18 करोड़ और मकान आपने बनवाए 4 लाख 50 हजार शहरों में और देहातों में मिलाकर। क्या है यह? यह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है, जितनी बड़ी ममस्या हमारे देश की है उसको देखते हुए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर आप सचमुच में समस्या का समाधान करना चाहते है तो कुछ करें। शहरों के लोगों को आप जानते हैं, शहर में कौन लोग रहते हैं---सरकारी कर्मचारी जिनकी लाखों की संख्या है, अस्पतालों में काम करनेवाले, खुद दिल्ली के अस्पताल में काम करनेवाले जो कल मंत्री महोदय के यहां प्रदर्शन लेकर गये थे उनकी मांगों में एक मांग आवास की भी है, तो वे अस्पतालों में काम करनेवाले हजारों और लाखों कर्मचारी हैं, उद्योगधन्धों में काम करनेवाले लाखों और करोड़ों कर्मचारी हैं, मध्यमवर्गीय

[श्री रामावतार शास्त्री]

कर्मचारी जो बैंकों में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, दूसरे सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में काम करते हैं और पत्रकार जिन्हें हमारे देश में चतुर्थ स्टेट माना जाता है, पूरे देश के अन्दर पत्रकारों के आवास की समस्या भी है, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं, अपने को आज भी पत्रकार मानता हूं, तो मैं जानता हूं, वर्षों काम करने के नतीजे के तौर पर मैंने देखा है कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और साधारण नागरिक, झुग्गी झोंपड़ी वाले हों या दूसरे लोग हों, तमाम वे लोग जो साधारण काम करते हैं, एक रुपया दो रुपया रोज कमा लेते हैं। अभी रेलवे उप-मंत्री महोदय कह रहे थे कि मजदूरों को कम से कम 148 रुपया देते हैं, ऐसे लोग भी शहरों में रहते हैं, कम पैसा कमाने वाले, रुपया रोज, दो रुपया रोज कमाने वाले हजारों और लाखों की तादाद में रहते हैं, उनकी समस्या है। इसलिए यह समस्या बड़ी विशाल है। और आपने अभी तक लोन देने के जो कानून बनाए हैं, आप लोन देंगे लेकिन किनको देंगे ? जो लोन अदा करेगा। गरीबों को नहीं देंगे जो दाने दाने को मोहताज हैं, जो अपने बच्चों को दवा नहीं दे सकते, उनसे आप लोन लेने की उम्मीद कर सकते हैं ? वे बेचारे हिम्मत भी नहीं कर सकते आपकी शर्तों को मान कर मकान बनवाने की। तो यह समस्या है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि गरीबों को जिनकी स्थिति बड़ी साधारण है, जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है उन्हें केवल किराये पर मकान देने व्यवस्था आपको करनी चाहिए और किराये से आप पूंजी खुद वसूल लेंगे। समाजवाद की बात करते हैं तो इस तरह से कदम उठाने से सचमुच में लोगों को कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया है। आप बड़े लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। 200 करोड़ रिवाल्विंग फण्ड को बढ़ा कर उसे कई हजार करोड़ बनाना चाहते हैं। तो आपकी सरकार की नीति देश के अन्दर पूंजीवाद बनाने की है, जब कि आप समाजवाद का नारा दे रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है, सबूत है कि आप शहरों में मकान उनको देना चाहते हैं जो स्वयं पहले से मकान मालिक हैं। आप कहीं भी चले जायं---जहां जहां कालो-नीज बन रही हैं, बड़े बड़े अधिकारियों ने, पैसेवालों ने, जिन्होंने काला धन छिपा रखा है, जिन्होंने घूस से पैसा कमाया है, वे ही मकान बना रहे हैं, किराया कमाने के लिए मकान बना रहे हैं। पटना में चलिये---हैदर इमाम साहब की मार्केट है, हथुआ मार्केट है, बड़े बड़े जमींदारों और पैसेवालों ने उनको बनाया है और लाखों रुपया कमा रहे हैं और आप भी उन्हीं की मदद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों की मदद करना छोड़िये।

दूसरा सवाल इसी से सम्बन्धित है---शहरों की गन्दी बस्तियों की सफाई या उनमें सुधार लाने का। यह बहुत बड़ा मसला है। बड़े बड़े शहरों में लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं, झोंपड़ियों को गन्दी जगहों पर बनाते हैं, जिस का उनके स्वास्थ्य और दूसरे नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मैं पटना के बारे में जानत हूं---पटना इतना बड़ा गन्दा शहर है कि शायद हिन्दुस्तान में कोई शहर इतना गन्दा नहीं मिलेगा। वहां का स्लम एरिया बहुत बड़ा एरिया है। वहां के लोग इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं---दक्षिण पटना नागरिक समिति इस क्षेत्र में काफी काम कर रही है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आप राज्य सरकारों को मदद तो देते हैं, लेकिन पूरी तरह से मदद नहीं करते, आप शत-प्रतिशत पैसा देकर उनकी मदद कीजिये तभी आप इस समस्या को हल कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि

आप साफ साफ जवाब दीजिये, घुमा-फिरा कर नहीं। कुछ छिपाइये नहीं, धनियों की वकालत यहां पर न कीजिये। समाजवाद का नारा आप लगा रहे हैं, लेकिन हमें तो विश्वास है कि समाजवाद आपसे नहीं आयेगा, हिन्दुस्तान में समाजवाद यहां की गरीब जनता, किसान और मजदूर संघर्ष करके, आन्दोलन चलाकर और देश के इजारेदारों, पूंजीपतियों का तख्ता पलट कर स्थापित करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं :—

1. चौथी योजना में आप कितने गृह, कितने आवास बनाएंगे तथा उन पर कितनी रकम खर्च करने की आपकी योजना है ?

2. सुना है कि इस काम में विदेशी मदद करना चाहते हैं, ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है और आपने कहा है कि हम वह मदद नहीं लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी राष्ट्र भी इस योजना में मदद करना चाहते हैं, यदि हां, तो उन राष्ट्रों के नाम क्या हैं और सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा आपकी क्या शर्तें हैं ?

3. क्या सरकार गृह-विहीनों को मकान बनवा कर किराये पर देने की कोई योजना क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि अभी तक आपकी ऐसी कोई योजना नहीं है तो हम चाहेंगे कि आप इस पर विचार करें।

4. औद्योगिक मजदूरों के लिये अनिवार्य रूप से आवास की व्यवस्था करने का क्या कोई कानून सरकार बनाने का विचार रखती है, जिससे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मजबूर किया जा सके कि वे मजदूरों के लिए आवास बनायें ?

5. शहरों में जमीन की खरीद और बिक्री बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कौन खरीदता है—गरीब नहीं खरीदता, अमीर खरीदते हैं। क्या आप इस पर रोक लगायेंगे तथा सब के लिये—धनी हो या गरीब—तमाम लोगों को बराबर जमीन मिले, ज्यादा से ज्यादा 500 स्केवेअर-फीट जमीन मिले—क्या ऐसी किसी योजना पर विचार करना चाहते हैं ? यदि नहीं करना चाहते हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

यदि आपने मेरे इन प्रश्नों का ठीक से जवाब दिया तो मुझे मालूम होगा कि आप वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं, वरना ढोल में पोल के सिवाय और कुछ नहीं होगा।

एक प्रश्न और है—जो बड़े बड़े मकान हैं, जैसे मैंने बताया पटना में हैदर इनाम की मार्केट, हथुआ मार्केट दिल्ली में भी ऐसी बड़ी बड़ी मार्केट्स होंगी। क्या इन मकानों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना पर आप विचार करना चाहते हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

इन प्रश्नों के उत्तर से समाजवाद की पोल खुलनेवाली है।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, आधे घन्टे की चर्चा का यह प्रश्न मेरा था, लेकिन हमारे शास्त्री जी महाराज इस को ले उड़े, फिर भी मैं उन को धन्यवाद देता हूं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बड़े बड़े शहरों में जो गन्दी बस्तियां हैं, हम उन्हें हटा कर, उन की जमीनों पर वर्टिकल मकान बनायेंगे। इस के प्रत्युत्तर में मेरा सुझाव था कि आप गरीबों के स्लम पर मकान बनाने की योजना बना तो रहे हैं, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों में बड़े बड़े अफसरों और मिनिस्टरों के बंगलों में भी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, क्या उन बंगलों को हटा कर उन की जगह वर्टिकल मकान बना कर उन लोगों को भी फ्लैट्स में रहने के लिये बाध्य करेंगे ताकि उन जमीनों

[श्री वेणीशंकर शर्मा]

पर भी गरीबों के आवास की व्यवस्था हो सके ?

अब मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार चाहती है कि मकान बनाये जांय, लेकिन सवाल पैसों का है। मांगने से कर्ज नहीं मिलता है। भिक्षा मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती है। अभी-अभी शास्त्री जी ने कहा है कि ब्लैक मार्केट करने वाले और अफसर लोग मकान बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वे लोग मकान नहीं बना रहे हैं, न बना सकते हैं क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो इन्कम टैक्स वाले उन के सर पर सवार हो जायेंगे कि यह पैसा कहां से लाये···

श्री रामावतार शास्त्री : आपको हम ऐसे हजारों केस दिखला सकते हैं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : फिर तो आप फाइनैन्स मिनिस्ट्री को कहिये कि वे उन पर टैक्स लगायें। मैं निवेदन कर रहा था कि लोगों के पास पैसा है। मैंने मंत्री जी को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है, कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन फाइनेन्स मिनिस्ट्री के डर से नहीं निकल रहा है। हमें इस से कोई सरोकार नहीं है कि फाइनेन्स मिनिस्ट्री उन से टैक्स वसूल करती है या नहीं करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में जो पैसा है, वह देश के काम आये, सदुपायोग में आये, चाहे आप उन से टैक्स के जरिये लें या न लें और अगर आप में टैक्स लेने की ताकत नहीं है तो हम से कम मोरिटीरियम को दें कि जितना पैसा वे मकान बनाने में लगायेंगे, उस पर सरकार कोई हमसे सवाल नहीं करेगी, और इन मकानों को बनाकर उन्हें आप सस्ते किराये पर लोगों को दें।

बैलजियम में, उपाध्यक्ष महोदय, लड़ाई के बाद मकानों की इसी तरह की बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने उस को इसी तरह से थोड़े समय में हल कर लिया। इस लिये में मंत्री जी से इन तीन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं—खासकर क्या वह फाइनैन्स मिनिस्ट्री को सलाह देंगे कि जिन पैसों का वे टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत सा पैसा अफसरों के पास है, देश में बहुत से डैम्ज बने हैं, कई पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं, जितना रुपया इन पर खर्च हुआ है, उस के अनुपात में जितना रुपया टैक्स से आना चाहिये था, वह नहीं आया है, वह लोगों के पास पड़ा हुआ है, उस को किसी प्रकार से मकान बनाने के काम में नियोजित करा सकेंगे या नहीं ?

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : शर्मा जी ब्लैक मनी को व्हाइट कराना चाहते हैं।

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शास्त्री जी को इस प्रश्न को यहां उठाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। आज सुबह जब इस सवाल पर यहां बहस हो रही थी, मंत्री महोदय ने खुद बताया था कि इन बेघर लोगों के लिये मकानों की समस्या का समाधान करने के लिये 33 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। लेकिन मैं मंत्री महोदय को याद दिलाऊं कि जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था, पटना शहर में भूमिहीन लोगों को बसाने के कि लिये 9 एकड़ जमीन दी गई थी। यह दो साल पहले की बात है, जब वहां गैर-कांग्रेसी सरकार आई तो उसने देखा कि बजाय इस के कि उस पर भूमिहीन लोग मकान बनायें, उस पर सब बड़े बड़े लोगों ने मकान बना लिये और उस के बाद इस की जांच करने के लिये एक हरिहर महापात्र कमेटी मुरर्रिर की गई। मैं जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है। शाह साहब बतायें—पटना शहर में जो रुपया बेघर लोगों के लिए मकान बनाने के

लिये रखा गया था क्या उसके ऊपर जज और दूसरे बड़े बड़े लोगों ने मकान बना लिए पटना शहर में लेकिन जो गैर कांग्रेसी सरकार वहां पर बनी थी उसके चलते एक जांच कमेटी (महापात्र कमेटी) बिठाई गई थी तो मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी बतायें कि उसके ऊपर क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के दिमाग में एक उलझन में है, मेरी उनके साथ सहानुभूति है मैं जानता हूं कि यह मामला बहुत पेचीदा है मैं जानकारी के लिए मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि डेढ़ साल पहले स्पीकर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल में हम रूस गए थे। वहां जाकर देखने पर हम दंग रह गए। मैं तारीफ करना चाहता हूं कि ताशकन्द जोकि उजबेकिस्तान की राजधानी है वहां एक भूकम्प में आधा शहर समाप्त हो गया था लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 6 महीने के अन्दर सारे बेघर लोगों के लिए मकान बना दिये गये। तो मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह एक क्रान्तिकारी सवाल है और इसके लिए क्रान्तिकारी समाधान की भी आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय से यह उम्मीद करें कि वे हिन्दुस्तान में ऐसा कानून बनायेंगे कि पांच व्यक्तियों के हर परिवार के लिए एक घर रहे और एक से ज्यादा जिनके मकान हों क्या उनको सरकार राष्ट्रीयकरण करेगी ?

दूसरी बात यह है कि कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अंग्रेजों के जमाने में कैन्टनमेन्ट के इलाके चले आ रहे हैं। कुछ बड़े साहब लोग कैन्टूनमेन्ट इलाके में रहा करते थे। बम्बई, कलकत्ता वगैरह में बड़े लोगों को घोड़ा खेलने के लिए कितने ही मकान पड़े हुए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कैन्टूनमेन्ट में हार्स रेस के लिए जो जमीन और मकान खाली पड़े हैं जिसमें कि हजारों लोग बस सकते हैं क्या उसका सरकार राष्ट्रीयकरण करेगी ? ये मेरे तीन सुझाव हैं, इन के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय की क्या राय है ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : I am grateful to the Members for raising these questions. I am also grateful to them for seriously discussing this qurstion apart from a little repartee here and there.

It is entirely correct that if the entire housing shortage both in the rural and urban areas is to be looked after, Rs. 33,000/- crores will be necessary. Shr Shastri posed a qnestion. 5 करोड़ का 8 करोड़ रुपया आपने बना लिया, वह तो गरीबों के पास से आता है, यह बात ठीक नहीं है तो एक एक्सपेरिमेन्ट हमने किया था और इस ढंग से किया कि जो कार्मशियल एरिया है उसको आक्शन में देने से ज्यादा पैसा मिलता है—यह बात सही है लेकिन कार्मशियल एरिया से जो पैसा मिलता है उसका उपयोग गरीबों को सब्सीडाइज करने में करते है। ..

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कितना किया है, बताइये।

श्री के० के० शाह : मैं बताऊंगा। यह काम ऐसा नहीं है जिसको कोई अकेले कर सकता है। एक पार्टी कर सकती है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। इसमें आप सब का सहयोग नहीं मिलेगा तो यह काम कभी पूरा नहीं होगा।... **(व्यवधान)**.....

श्री रवि राय : अच्छे काम के लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री के० के० शाह : आपने देखा होगा कि पहले हम 80 गज देते थे और इसके लिए देते थे कि जो क्वार्टर है वह उसको फोकट में

[श्री के० के० शाह]

दिया जाये। इसके ऊपर एक हजार रुपया खर्च किया जाये जिसको अभी 1200 रुपया किया है। कम से कम किराया लिया जाता है। इसके बाद जब मांग बढ़ गई तो हमने 80 का 40 गज कर दिया। लेकिन जो इनएलिजिविल थे, 67 तक इनको गिना और उसके बाद जो इन-एलिजिविल थे उनके लिए भी 800 रुपया खर्च करने के लिए तय किया गया तो वह रुपया कहां से आता है? जो पैसा आता है उसी का इसमें उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका सहारा चाहते हैं। जहां आपको दिखाई पड़े कि इसका उपयोग पैसेवाले करते हैं तो आप हमारे कान खींचिये। लेकिन जहां पैसा कमा कर मैं गरीबों के लिए उपयोग करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि दो सौ करोड़ का हाउसिंग रिवाल्विंग फण्ड है इसमें हम दो कमरे या तीन कमरे से ज्यादा बनानेवाले नहीं हैं। लेकिन आप यही कहेंगे कि पैसेवालों के लिए उपयोग हो गया जैसा कि आपने कहा (**व्यवधान**)··· जैसा कि आपने कहा कि स्लम एरियाज का क्या करेंगे, आप जानते हैं कि बम्बई और कलकत्ता में मैंने जाकर देखा है (**व्यवधान**)···

श्री रामावतार शास्त्री : पटना भी देखा है या नहीं?

श्री योगेन्द्र शर्मा : जो मकान बना रहे हैं उनके एलाटमेण्ट में फोर्थ ग्रेड एम्प्लाईज को प्रायर्टी देंगे?···(**व्यवधान**)···

श्री के० के० शाह : आपको बताऊंगा। एक दफा आपके और हमारे, दोनों के बीच में समझदारी पूरी हो जाये तो फिर सहयोग भी पूरा मिलेगा। यह काम ऐसा है जिसमें आपको भी दिलचस्पी है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से पैसा दिया है, जब आप जानेंगे तो आप धन्यवाद देंगे क्योंकि फोर्थ प्लान बन जाने के नजदीक आ गया था जबकि हम सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स मिले। जो हाउसिंग मिनिस्टर्स हैं उसमें सभी पार्टी वाले हैं और सभी स्टेट्स के हैं। सभी हाउसिंग मिनिस्टर्स ने यूनानिमसली तय किया था इसमें बंगाल भी इंक्लूडेड है और उड़ीसा, दिल्ली, कैरल और महाराष्ट्र भी इनक्लूडेड है। सबने मिलकर तय किया कि एक ही तरीका है और जब हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो फोर्थ प्लान पूरा होने जा रहा था और यह कहा जाता था कि इससे तो इनफ्लेशन होगा लेकिन हमने बताया कि इनसे इनफ्लेशन नहीं होता है बल्कि डिफ्लेशन होता है। और जैसा कि आपने शहरों के लिए कहा, देहात के लिए भी यही करना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन की जो बात है उसमें दो हजार करोड़, या जो भी आप हिसाब लगायें, उतने का जो गल्ला पैदा होगा उसमें भी सेविंग करने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। यह गल्ला जो बढ़ेगा और लोगों को जो पैसा मिलेगा, अगर उसका आपने उपयोग नहीं किया तो कंजूमर गुड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जिससे उसके दाम भी बढ़ेंगे। इसमें हाउसिंग ही एक ऐसी चीज है जो कि पैसा खींचने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट्स की तनख्वाह अगर 700 से 800 हो गई – मैं यह नहीं कहता कि डीयरनेस एलाउन्स बढ़ा दिया---उनसे अगर कहा जाये कि सौ रुपये का इंस्टालमेण्ट देते जाओ तो बीस साल के बाद मकान तुम्हारा हो जायेगा तो वह भी घर में अपनी बीबी को समझा सकेगा कि भाई कुछ भी करो, किसी तरह से तकलीफ करके सौरुपया बचाओ ताकि सर्विस के बाद मकान अपना हो सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह डिफ्लेशनरी है। तो उन्होंने हमारी बात मानी।

अब दो सौ करोड़ में 33 हजार करोड़ की मांग कैसे पूरी हो सकेगी तो जैसा मैंने बतलाया कि जो स्लम एरियाज हैं बम्बई और कलकत्ता में··· (**व्यवधान**)···

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कानपुर को मत भूलिये ।

श्री के० के० शाह : कानपुर को भी इन-क्लूड किया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : और पटना को भी ?

श्री के० के० शाह : पटना भी इन्क्लूडेड है।

तो स्लम एरियाज से ट्रानजिट कैम्प्स में वहां की आबादी को ले गये और वहां सारे मकानों को गिरा कर वर्टिकल कांस्ट्रक्शन करके वहां की एक बटा पांच जो आबादी है उसको वहां रख सकेंगे । अब आप कहेंगे कि चार बटा पांच एरिया जो बचे उसका भी गरीबों के लिए उपयोग करो तो मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि मुझे उसको बेचने दीजिये लेकिन उसका पैसा हम गरीबों के लिए ही देंगे । मुनाफा कमाने के लिए वह पैसा नहीं रखेंगे । ये मकान जो बनवायेंगे उसके नीचे कामर्शियल शाप्स को आक्शन से देनेवाले हैं लेकिन जो फायदा होगा उसको ऊपर रहनेवालों को सब्सी-डाइज करने के लिए करेंगे । आप कहेंगे कि इसमें भी मध्यम वर्ग की दुकानें चली जाती हैं इसलिये उनको भी उसी ढंग से दे दो । तो इस तरह से कहीं न कहीं कठिनाई आयेगी ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मध्यम वर्ग को दीजिए लेकिन बड़े बड़े लोगों को मत दीजिए ।..... **(व्यवधान)**.....

श्री के० के० शाह : मैं दिल्ली की बात तो नहीं कह सकता लेकिन बम्बई की बात करूंगा, बम्बई में जो मकान हैं उस पर रैन्ट कंट्रोल ऐक्ट लगाया है । .....**(व्यवधान)**... एक नया ऐक्ट अभी लगाया है । बिल्डिंग रिपेयर्स से लगाया है—जिसके मकान अच्छे हैं उनके ऊपर भी लगाया गया है और ऐसे मकानों के ऊपर भी लगेगा और जो पैसा आयेगा वह रिपेयर्स में लगाया जायेगा ।...**(व्यवधान)**...

19.00 hrs.

श्री स० मो० बनर्जी : पगड़ी का पैसा कहां लगेगा ? ...**(व्यवधान)**.....

श्री के० के० शाह : पगड़ी की बात आपने ठीक कही । आफिशली मेरे पास सबूत नहीं होगा लेकिन अनआफिशली में यह बात मानने के लिए तैयार हूँ । मगर जो आदमी 10 हजार रु० पगड़ी के देता है, यदि उस को हम 7-8 हजार में दो कमरे का मकान दे देते हैं तो वह पगड़ी नहीं देगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : 10 हजार रु० की पगड़ी कौन देता है ? धनी लोग ।

श्री के० के० शाह : नहीं, नहीं । शास्त्री जी हमारे साथ चलें । मैं फुटपाथ वालों की बात कह रहा हूँ । आप यहाँ पर भी देखिये । जो मकान बनाये गये दिल्ली की हुकूमत के द्वारा जब उसके लिए अर्जियां मांगी गईं तब आपको ताज्जुब होगा कि मध्यम वर्ग के लोगों से दो हजार मकानों के लिए दस हजार मकानों की मांग आ गई । तो जो बात आप कह रहे हैं वह नहीं है । लोग आते हैं । मान लीजिए घर का एक आदमी कमाता है, उसका बच्चा बड़ा हो गया है, उसके रहने के लिये जगह नहीं है, तो कुछ करके, मेहनत करके, कहीं से लाकर पैसा दे देता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से बतलाना चाहता हूँ कि इस वक्त मौका है । इस हाउस में कम से कम हम और आप हैं और जन संघ के वह नुमाइन्दे हैं जो हमारे साथ हैं । इस वक्त पास करा लीजिये, वह ऐबसेंट हैं ।

श्री के० के० शाह : मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सबका सहयोग हमें मिला है । मैं कोई पार्टीबाजी की बात इसमें नहीं करना चाहता हूँ । यह बड़ी डिफिकल्ट प्राब्लेम है और सबको साथ लेकर हमको चलना चाहिये ।

अगर हम भूलेश्वर में जायेंगे तो देखेंगे कि कोई भी पैसे वाला वहां पर रहने नहीं आयेगा ।

[श्री के० के० शाह]

वह जगह हम गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है। वहां पर दो तीन कमरे लेने के लिये पैसे वाले नहीं आते हैं। स्क्वेटर्स के बारे में वह बहुत वैलुएबल लैंड है। अभी हमने बम्बई के लिये एक स्कीम चलाई है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I want to draw the attention of the Minister to the fact that it is 7 O' clock.

SHRI K. K. SHAH : I am grateful to you. श्री शास्त्री ने सवाल किया है :

How many houses will be constructed in the fourth Plan ?

मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि 1 करोड़ रु० में 5,000 मकान बनेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिये।

श्री के०के० शाह : हमने एक कमेटी बनाई है। दो तीन प्रकार के सिस्टम बने हैं। हालो ब्लाक्स, हालो बीम्स वगैरह जिसमें खर्च अगर हम 22 रु० से 13 रु० पर ला सके, कमिटमेंट न हो जाये इसलिये मैं कहता हूँ कि ला सके, तो ठीक है। अगर यह कंस्ट्रक्शन तीन महीने में न हो सके, 18 महीने, 12 महीने या 9 महीने लगें तो इसको हम पूरा नहीं कर पायेंगे, अगर तीन महीने में हम कंस्ट्रक्शन को कर सकें तो यह रिवाल्विंग फंड सचमुच में रिवाल्विंग फंड बन जायेगा। लेकिन इसके लिए मार्डन मेथड अपनाने होंगे, मेकेनाईज्ड फेक्ट्री बनानी पड़ेगी, किल्न से काम नहीं चलेगा। जैसा रशिया में है कि they are able to construct in less than a month. वह करना चाहिए।

दूसरे आप ने कहा कि : How many countries wish to help ?

पहले तो हमारे तहां जो रिवाल्विंग फंड रक्खा गया है उसके लिये मैं कहना चाहता हूँ कि सब जगह से हमें मदद मिलेगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसमें दिलचस्पी दिखलाई है।

श्री रामावतार शास्त्री : सुना है वर्ल्ड बैंक ने 75 करोड़ रुपये देने के लिए कहा है ?

श्री के० के० शाह : आप 75 करोड़ से ही क्यों राजी हो जाते हैं ? इससे हमारा काम नहीं चलेगा। यह 200 करोड़ से 400 करोड़ तक होना चाहिये।

यह बात ठीक कही गई कि मिनिस्टर के मकान हैं, सेक्रेट्रीज के मकान हैं, इन मकानों की जमीन बहुत वैलुएबल है। प्राइम मिनिस्टर ने परसों जवाब दिया था कि इसके दाम ज्यादा मिलते हैं तो हमको फ्लैट लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा किस ढंग से हो सकता है यह हमें सोचना है। ऐसा नहीं है कि अकेले करने से यह काम होगा। सबको साथ रहना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद ऐसा भी एक दिन आ सकता है जब पार्लियामेंट के मेम्बरों से कहूँ कि भैया, आप भी...

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : आप हम को छोटे फ्लैट दे दीजिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(**व्यवधान**)... ..

श्री के० के० शाह : The Deputy-Speaker has been kind enough to give me the time. As I have said, so far as rents are concerned, we will try to subsidise in the manner I have stated. Profitering in land, दिल्ली में बहुत सारी जमीन एक्वायर हो गई है, और लैंड रहेगी इसके लिए आपने टेक्स्ट देख लिया है।

हमें इसके बारे में भी सोचना है कि सीलिंग किस ढंग से हो सकती है। अगर कोई लीगल

कठिनाई इसमें है तो उसके लिए भी रास्ता मिल जायेगा। इसमें उनको पैसा कमाने को नहीं मिलेगा ऐसी हमको आशा करनी चाहिये और इसका मैं विश्वास दिला सकता हूँ।

श्री के० के० शाह : इसके बाद श्री शर्मा ने कहा...

श्री रामावतार शास्त्री : इंडस्ट्रियल लेबर के लिए कम्पल्सरी हाउसिंग स्कीम की बात बतलाइये।

श्री के० के० शाह : हमने इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिये ग्रान्ट और लोन दोनों के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि किस ढंग से हो सकता है। **लेट मी सी व्हाट इज लीगली फीजिबल**, लेकिन जैसा मैंने कहा एक तरीका हो सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : एक दफा कर लीजिए और सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिये।

श्री के० के० शाह : एक बात उन्होंने कही कि जो ब्लैक मनी है उससे वह मकान बना दें। यह नहीं पूछना चाहिए कि कहां से उसको बनाया गया। कैसे क्या हो सकता है, यह मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचना होगा कि कैसे क्या हो सकता है। कुछ भी हो जल्दी से करना चाहिये।

SHRI BENI SHANKAR SHARMA : Whether you beg, borrow or steel, we must have houses.

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम लोग किसी के मकान पर दखल कर लें तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। वह कहते हैं कि **बारो, और स्टील** : हम बिड़ला के मकान पर कब्जा कर लें तो कोई नहीं पूछेगा। **(व्यवधान)**

श्री के० के० शाह : श्री रवि राय ने कहा जो कुछ, उस में कुछ पार्टीबाजी की बात आ गई है। इस तरह से नहीं कहना चाहिये। सब स्टेटों ने किया है, किसी पार्टी की भी स्टेट लो। हम ने पैसा दिया है उसका उपयोग नहीं किया गया है। हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं...

श्री रामावतार शास्त्री : आप खुद योजना बनाइये।

श्री के० के० शाह : आप सब नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल में हमें चीफ मिनिस्टर की कैसेट दिला दीजिये।

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग तो वहां बैठने जायेंगे नहीं, रहेंगे तो आप ही न ?

श्री के० के० शाह : ठीक कहा, ताशकन्द में उन्होंने छः महीने में तैयार कर दिया। यह मेकेनाइज्ड प्रोसेस से ही हो सकता है, बिना मेकेनाइज्ड प्रोसेस से नहीं हो सकता। कैंटोमेंट एरिया में यह नहीं होगा। यहां पर हम कोई काम नहीं करेंगे।

आखिर में मैं शुक्रगुजार हूं सब लोगों का यह बड़ा कठिन काम है और इस में हम को पूरा सहयोग मिला है। सब स्टेटों का सहयोग मिला है। अगर इसी ढंग से सहयोग मिलेगा तो 200 करोड़ से बढ़ा कर यह 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ हो जायेगी और इस का उपयोग गरीबों के लिये होगा, अमीरों के लिये नहीं।

19.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 10, 1970/Phalguna 19, 1891 (Saka).